।। श्री गणेशाय नमः।।

हिन्दी पाक्षिक Fortnightly

बात हिन्दुस्तान की

BAAT HINDUSTAN KI

RNI No.: WBHIN/2021/84049

विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ अमावस्या, 16-31 मई 2026 (16-31 MAY 2026), वर्ष -6 (YEAR - 6), अंक - 02, पृष्ठ - 4, मूल्य - ₹2, (PRICE - 2/-)

बंगाल में पहली भाजपा सरकार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का पीएम से लेकर 22 राज्यों के सीएम बने गवाह

सोनू कुमार झा, कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर बंगाल की सत्ता में पहली बार आई भाजपा की पहली सरकार का शनिवार को यहां भव्य शपथ ग्रहण समारोह किसी राजनीतिक उत्सव से कम नहीं था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित शपथ समारोह का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता गवाह बने। इन दिग्गजों की उपस्थिति में सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बंगाल में भाजपा के वह पहले मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ श्याम प्रसाद मुखर्जी की धरती पर भाजपा राज का आगाज हो गया।

यह सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुति और राजनीतिक संदेशों का संगम था।

मंच पर एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद रहा

मंच पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व व एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद था। भाजपा शासित राज्यों के सभी उपमुख्यमंत्री भी समारोह में मौजूद रहे। यह दृश्य भारतीय राजनीति में विरल माना जा रहा है, जहां एक राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह को राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का मंच बना दिया गया। जहां देश का पूरा पावर सेंटर एक मंच पर इकठ्ठा हुआ। संभवतः देश में यह पहला मौका है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पीएम से लेकर एक साथ 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति रही है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष (बंगाल के हावड़ा निवासी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष) और हाल में बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी इस ऐतिहासिक समारोह के गवाह बने।

योगी से लेकर सम्राट तक सभी रहे मौजूद

भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस, बिहार से सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश से मोहन यादव, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, राजस्थान से भजन लाल श्र्मा, असम से हिमंत बिस्व सरमा, ओडिशा से मोहन चरण माजी, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली से रेखा गुप्ता, गोवा से प्रमोद सावंत व अन्य उपस्थित रहे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश से एन चंद्रबाबू नायडू, नागालैंड से निफ्यू रियो, सिक्किम से प्रेम सिंह तमांग व अन्य मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, राजस्थान से दिया कुमारी, महाराष्ट्र से सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्रियों में शाह व राजनाथ के अलावा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण व वन मंत्री एवं बंगाल भाजपा के चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री जितनराम माजी उपस्थित रहे। इसके अलावा भाजपा के अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बंगाल भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक व पार्टी को प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल और मंगल पांडेय मौजूद रहे।

बांग्ला फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं

बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बांग्ला फिल्म और मनोरंजन उद्योग की कई प्रमुख हस्तियां भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उपस्थित रहीं। दिग्गज अभिनेता प्रसनजीत चटर्जी समारोह में सफेद कमीज पहने नजर आए। अभिनेता जीत सुबह जल्दी ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। राजनीतिक कार्यक्रमों से आमतौर पर दूर रहने वाले जीत की उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अभिनेता जिस्सू सेनगुप्ता भी समारोह में हल्के भूरे रंग की कमीज और काला चश्मा पहने नजर आए।

अन्य उपस्थित लोगों में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती और नृत्यांगना ममता शंकर शामिल थीं। ममता शंकर ने कहा कि मेरी बस यही कामना है कि हमारे राज्य में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए, कुछ अच्छा और सकारात्मक हो। अभिनेता ऋषि कौशिक भी बंगाली टेलीविजन उद्योग के कई कलाकारों के साथ उपस्थित थे। लाखों की भीड़, भगवा झंडों की लहर, जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारों के बीच यह आयोजन एक जन-उत्सव में बदल गया।

बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में 'वंदे मातरम' का गायन हुआ अनिवार्य

ब्यूरो कोलकाता : बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य कर दिया है। बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि आगामी सोमवार (18 मई) से राज्य के सभी स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में 'वंदे मातरम' की शुरुआत की जाएगी। इस बाबत बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को ही एक आधिकारिक आदेश जारी कर कहा कि राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य होगा। शिक्षा निदेशक द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कक्षाओं की शुरुआत से पहले सुबह की प्रार्थना में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य किया जाना चाहिए। निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को राष्ट्रगीत के गायन में भाग लेना होगा। संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

यह कदम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने की पहल के कुछ समय बाद आया है। केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना एक दंडनीय अपराध बन जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बंगाल के स्कूलों में पारंपरिक रूप से केवल रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान 'जन गण मन' और राज्य गान 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल' ही गाया जाता था। अब इन दोनों के साथ 'वंदे मातरम' का गायन भी अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि स्कूल अधिकारियों को इस कार्यान्वयन के प्रमाण के रूप में वीडियो रिकार्डिंग सहित पूरी कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करने के लिए भी कहा गया है।

पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में रवींद्र नाथ टैगोर द्वारा ही लिखे गए गीत 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' को हाल के वर्षों में राज्य गीत के रूप में पेश किया था।

यूनिफार्म वितरण पर लगी रोक

इसके साथ ही, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वितरित किए जाने वाले स्कूल बैग और यूनिफार्म के वितरण पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

बंगाल में सरकार गठित करते ही भाजपा अगले लोस चुनाव की तैयारियों में जुटी।

सोनी कुमारी झा: बंगाल में सरकार गठित करते ही भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उसने अपने पहले मंत्रिमंडल के गठन से यह स्पष्ट कर दिया है। सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री और दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निशिथ प्रमाणिक, अशोक कीर्तनिया व खुदीराम टुडू को मंत्री बनाकर पार्टी ने जाति, क्षेत्र, संगठन और सामाजिक समीकरणों को एक साथ साधा है।

जंगलमहल से पूरे बंगाल का चेहरा

नंदीग्राम के भूमिपुत्र सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने सबसे बड़ा संदेश दिया कि आंदोलन और संगठन चलाने वाला नेता ही सरकार का नेतृत्व करेगा। सुवेंदु की ताकत पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया का जंगलमहल इलाका है, जहां हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 38 में से 34 सीटें जीतीं। संदेश साफ है ममता के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को मुख्यमंत्री बनाकर तृणमूल

कांग्रेस के कोर मतदाताओं व कार्यकर्ताओं में सेंध लगाना।

पुराने कार्यकर्ताओं व आरएसएस कैडरों को संदेश

वहीं खड़गपुर सदर से विधायक दिलीप घोष को मंत्री बनाकर भाजपा ने संगठन के पुराने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया है। 2015 से 2021 तक प्रदेश अध्यक्ष रहते घोष ने ही बंगाल में पार्टी को खड़ा किया था। घोष को मंत्रिमंडल में शामिल करके भाजपा ने आरएसएस के कैडरों को भी संदेश दिया कि संगठन की भूमिका सरकार में बराबर रहेगी।

महिलाओं को साधने की जुगत

आसनसोल दक्षिण से दूसरी बार विधायक बनीं अग्निमित्रा पाल बंगाल भाजपा की सबसे मुखर महिला चेहरा हैं। फैशन डिजाइनर से राजनीति में आईं अग्निमित्रा शहरी, पढ़ी-लिखी महिला मतदाताओं को आकर्षित करती हैं। उन्हें मंत्री बनाकर पार्टी ने महिला सशक्तीकरण और शहरी मध्यवर्ग की आवाज बनने का भी संदेश दिया है।

उत्तर बंगाल पर पकड़ और मजबूत करने की रणनीति

दिनहाटा से विधायक निशिथ प्रमाणिक को मंत्री बनाना उत्तर बंगाल पर भाजपा की पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। राजबंशी समुदाय से आने वाले निशिथ की उत्तर बंगाल की 30 में से 25 सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके निशिथ सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनके जरिए भाजपा ने राजबंशी मतदाताओं को संदेश दिया कि उत्तर बंगाल सरकार की प्राथमिकता में रहेगा।

मतुआओं के मत पर भी नजर

बनगांव उत्तर से विधायक अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाकर भाजपा ने मतुआ समुदाय को साधा है। मतुआ बंगाल की 17 प्रतिशत आबादी हैं और उत्तर 24 परगना व नदिया जिलों में निर्णायक हैं। कीर्तनिया खुद मतुआ समुदाय के धार्मिक आयोजनों में सक्रिय रहते हैं। भाजपा ने उन्हें कैबिनेट में रखकर सीमावर्ती इलाकों और शरणार्थी वोटरों को संदेश दिया कि नागरिकता कानून सिर्फ चुनावी वादा नहीं, नीति का हिस्सा बनेगा।

आदिवासियों का भरोसा जीतने की जुगत

रानीबांध के विधायक खुदीराम टुडू को मंत्री बनाकर भाजपा ने आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। जंगलमहल में आदिवासी वोटरों की संख्या निर्णायक है। 2021 में यहां भाजपा ने अच्छी बढ़त बनाई थी। 2026 में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है। खुदीराम की छवि शांत और जमीनी नेता की है। उनके जरिए भाजपा ने दिखाया कि आदिवासी विकास सरकार की प्राथमिकता में है।

अभिषेक बनर्जी का संदेश, संघर्ष जारी रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ हूं

सौरव झा: बंगाल में पहली भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम भावुक संदेश जारी किया और लिखा कि संघर्ष जारी रहेगा, कार्यकर्ताओं के साथ हूं। अभिषेक ने लंबी पोस्ट करते हुए चुनाव प्रक्रिया और मतगणना में अनियमितताओं के आरोप फिर दोहराए।

अभिषेक ने दावा किया कि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कई कार्यकर्ता घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि कहां क्या हो रहा है, मुझे सीधे बताइए। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने प्रभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात का आश्वासन भी दिया। अपने संदेश में अभिषेक ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली और बंगाल दोनों जगह भाजपा के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे की राजनीतिक रणनीति और आंदोलन की दिशा तय करेगी। मतगणना को लेकर भी अभिषेक ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग दोहराते हुए आरोप लगाया कि कई केंद्रों से तृणमूल एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था।

निगम के बिल्डिंग विभाग में 2000 करोड़ रुपये का घोटाला

अजय कुमार झा: वर्ष 2013 में हावड़ा नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के बोर्ड गठन के बाद उम्मीद जतायी जा रही थी कि अवैध निर्माण पर रोक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तृणमूल शासित बोर्ड के कार्यकाल में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हुआ और वर्ष 2013 से लेकर 2020 तक निगम इलाके में 3000 से अधिक अवैध निर्माण हुए हैं और निगम के बिल्डिंग विभाग में 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। "व्हिसल ब्लोअर्स" नामक एक संस्था ने संवाददाता सम्मेलन कर इस बात की जानकारी दी। सम्मेलन का आयोजन हावड़ा मैदान स्थित आइएमए हॉल में किया गया था। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था के सदस्य व सीनियर वकील सव्यसाची चटर्जी ने कहा कि वर्ष 2013 से 2020 तक शहरी अंचल में तीन हजार से अधिक अवैध निर्माण हुए हैं और इस काम में 2000 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। इस गबन में सिर्फ निगम के अधिकारी ही नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री अरूप राय सहित तमाम पूर्व पार्षद और प्रमोटर शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाली, उत्तर हावड़ा और मध्य हावड़ा में बिना किसी रोक-टोक के अवैध निर्माण हुआ है।

उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण होने के बाद निगम ने प्रमोटर से जुर्माना लेकर इसे वैध कर दिया, जबकि म्युनिसिपल एक्ट में यह गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि जब निगम अधिकारियों से आरटीआइ के तहत यह पूछा गया कि किस कानून के तहत अवैध निर्माण को वैध किया गया, तो निगम की ओर से यह जवाब दिया गया कि बड़े अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया गया। ये बड़े अधिकारी कौन हैं, यह पता लगाना अब जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि नयी सरकार इस संबंध में सही कार्रवाई करेगी। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहिए और समस्या का समाधान कानूनी तरीकों से होना चाहिए, न कि बुलडोजर से. सव्यसाची चटर्जी ने कहा कि जिन तृणमूल नेताओं ने अवैध निर्माण कर लोगों को फ्लैट बेचकर धोखा दिया है, उन नेताओं से हिसाब चुकता किया जाये। सम्मेलन में शामिल संस्था के सदस्य आत्म प्रकाश सिंह ने कहा कि जब हावड़ा नगर निगम और बाली नगरपालिका के बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों से अवैध निर्माण की सूची मांगी गयी, तो उनलोगों ने यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि प्रशासक ने मना किया है। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि जब धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा हो, तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र के विधायक को नहीं हो। ये विधायक भी निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य थे और सब कुछ इन नेताओं के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गयी है। कोर्ट ने निगम से अवैध निर्माण को लेकर जवाब मांगा है। नयी सरकार इस मसले को गंभीरता से ले और कड़ी कार्रवाई करे।

ठाकुरबाड़ी की ऐश्वर्यता में फैशन की लहर

गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरणीय बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक मॉडल और कलाकार उपस्थित रहे। कविगुरु ने अपने जीवन में कविता, कहानी और उपन्यासों के माध्यम से समाज के अनेक पहलुओं को उजागर किया, जो आज भी बंगालियों के लिए प्रासंगिक हैं। इसी प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए और उनके दर्शन से प्रेरित होकर एक अनूठे फोटोशूट का आयोजन किया गया। नवोदित और अनुभवी मॉडलों को साथ लेकर ऐतिहासिक शैली पर आधारित एक विशेष फोटोशूट और फैशन प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व टीना पात्र द्वारा संचालित 'टीना ग्लैम स्टूडियो' ने किया। इस अभिनव आयोजन ने मॉडलिंग जगत में पहले ही काफी चर्चा बटोर ली है। कार्यक्रम की मुख्य अवधारणा भारतीय परंपरा, संस्कृति और आधुनिक फैशन की बहुआयामी प्रस्तुति थी। बंगाली दुल्हन की पारंपरिक साज-सज्जा से लेकर राजस्थानी शाही परिधान, क्रिश्चियन ब्राइडल लुक, हेल्दी, वेस्टर्न और इंडो-वेस्टर्न स्टाइल— हर थीम को बेहद खूबसूरती और सटीकता के साथ प्रस्तुत किया गया। परिधानों की प्रस्तुति में बिदिशा बसु की रचनात्मकता ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। पूरे आयोजन की संचालिका और निर्माता टीना पात्र ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई प्रतिभाओं को बड़ा मंच देना और अनुभवी मॉडलों को नए कॉन्सेप्ट में प्रस्तुत करना था। पारंपरिक माहौल, आकर्षक सेट डिजाइन और भव्य रोशनी ने पूरे कार्यक्रम को शाही स्वरूप प्रदान किया।

संक्षिप्त डायरी

जेवर विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा:यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल वृद्धि प्रस्ताव निरस्त करने की मांग

नोएडा (एजेंसी) जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित टोल शुल्क वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है। विधायक ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया है। अपने पत्र में विधायक ने बताया कि विश्व वर्तमान में संवेदनशील आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। देश में पहले से ही ईंधन, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आम नागरिक आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे समय में यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क में वृद्धि से लाखों दैनिक यात्रियों, किसानों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने जोर दिया कि यमुना एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की प्रमुख जीवनरेखा बन चुका है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के कारण भविष्य में एक्सप्रेसवे पर यातायात और राजस्व में स्वाभाविक वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल टोल वृद्धि को जनभावनाओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता। विधायक धीरेंद्र सिंह ने प्राधिकरण और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जनहित, महंगाई और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित टोल वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए और इसे स्थगित अथवा निरस्त किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार और प्राधिकरण जनभावनाओं तथा सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील निर्णय लेंगे।

नोएडा में बस के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग:ऐप बनाया जाएगा

नोएडा (एजेंसी) नोएडा में सिटी बस सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच जल्द एमओयू साइन होने जा रहा है। पहले चरण में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनका न्यूनतम किराया 10 रुपए प्रस्तावित किया गया है। इन बसों के संचालन से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और जेवर एयरपोर्ट तक सफर करना आसान हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, बस सेवा मई के अंत तक शुरू की जा सकती है। ऐप से मिलेगा टिकट और पास, सबकुछ होगा पेपरलेस सिटी बस सेवा पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा, जिसके जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। मासिक और वार्षिक पास की सुविधा भी ऐप पर उपलब्ध होगी। पूरी व्यवस्था पेपरलेस रहेगी।

2 लाख लोगों को मिलेगा फायदा अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में करीब 2 लाख लोगों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। बसें खासतौर पर उन इलाकों में चलाई जाएंगी, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कम है या नहीं है। बसों का संचालन 15-15 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा। कुल 45 बसें नियमित रूप से चलेंगी, जबकि 5 बसें स्टैंडबाय में रखी जाएंगी। डबल डेकर बसें भी चलेंगी पहले चरण में 10 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। ये बसें बॉटेनिकल गार्डन से परी चौक तक चलेंगी। इसके अलावा 9 मीटर और 12 मीटर लंबाई की बसें भी अलग-अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। सिटी बसों के लिए सेक्टर-90 में आधुनिक बस डिपो तैयार किया जा रहा है। यहां ई-चार्जिंग स्टेशन, सर्विस सेंटर, ड्राइवर-कंडक्टर रेस्ट रूम और ऑफिस की व्यवस्था होगी। दिल्ली और गाजियाबाद तक जाएगी बस सेवा नोएडा की सिटी बसें सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेंगी। ये बसें दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार क्रइळ और गाजियाबाद तक भी जाएंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला, पिता-पुत्र गिरफ्तार:ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर मारपीट की थी मारपीट

नोएडा (एजेंसी) के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के पारसौल गांव में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पिता-पुत्र शामिल हैं, जिन्हें बुधवार को जेल भेज दिया गया। यह मामला पारसौल गांव निवासी मंजू द्वारा कोर्ट के आदेश पर दनकौर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। पीड़ित मंजू ने आरोप लगाया कि 4 अप्रैल को पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया, जिसमें परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर गज्जू उर्फ गजेंद्र, दीपांशु, यशू, प्रिंस, प्रेम सहित लगभग 10 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बुधवार को नामजद आरोपी गज्जू उर्फ गजेंद्र और उसके बेटे यशू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नोएडा रीजन में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 85.93 प्रतिशत:लड़कों का परिणाम रहा 73.91

नोएडा (एजेंसी) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार नोएडा रीजन में 12वीं का परीक्षा परिणाम 79.43 प्रतिशत रहा। नोएडा रीजन में कुल 1 लाख 23 हजार 490 स्टूडेंट्स ने रजीस्ट्रेशन करवाया। जिसमें से 1 लाख 22 हजार 322 स्टूडेंट ने परीक्षा दी। लड़कों का परीक्षा परिणाम 73.91 और गर्ल्स का परीक्षा परिणाम 85.93 रहा। देश में नोएडा रीजन 20वें स्थान पर रहा। वहीं 2025 में परीक्षा परिणाम 81.29, 2024 में 80.27 प्रतिशत रिजल्ट रहा। जबकि 2023 में 12वीं 90.27 प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए थे। 57 सेंटरों पर हुई परीक्षा नोएडा की बात करे तो यहां 57 सेंटर पर करीब 19 हजार से ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे। जिनकी परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हुई। इसमें से डीपीएस, एमिटी, रेयान, एपीएस, विश्वभारती पब्लिक स्कूल, बाल भारती, मार्डन के अलावा रेयान, लोट्स वैली, इंडस वैली, शिव नादर जैसे स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत रहा। यहां स्कूलों में परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स के चेहरों पर खुशी देखी गई। नहीं जारी होगी मेरिट लिस्ट इस बार भी 12वीं की परीक्षा परिणाम में स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। बताया गया कि अधिकांश स्कूलों में 85 प्रतिशत से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्कस 90 प्रतिशत से ज्यादा है। स्टूडेंट्स ने बताया कि मेरिट जारी नहीं होने से कंपटीशन का भाव समाप्त होता है। एक तरह से अच्छा और खराब दोनों ही है। फिलहाल काफी लंबे से स्टूडेंट्स परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा-ईंधन बचाना अब राष्ट्रीय जिम्मेदारी, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह

नई दिल्ली (एजेंसी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन बचाना और सार्वजनिक परिवहन को अपनाना देशहित में जरूरी कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से कार पूल, मेट्रो और बसों का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन बचाना और सार्वजनिक परिवहन को अपनाना देशहित में जरूरी कदम है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत को लेकर कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी अब जरूरत के मुताबिक ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है, जिसकी पहुंच पूरे एनसीआर तक है। ऐसे में लोग अगर निजी गाड़ियों की जगह मेट्रो, बस और कारपूल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण पर भी असर पड़ेगा। ये केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा अभियान है। जितने ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन अपनाएंगे, उतना ही बड़ा असर दिखाई देगा। सरकार विभागीय कामकाज में भी वाहनों की संख्या सीमित कर रही है। ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का इस्तेमाल करें और ऑफिस आने-जाने में कारपूलिंग को बढ़ावा दें।

नतीजों पर साफ दिखाई दिया डिजिटल पढ़ाई का असर, मोबाइल सहारा बना तो चुनौती भी

नई दिल्ली (एजेंसी) कई छात्रों ने ऑनलाइन नोट्स, यूट्यूब लेक्चर और मोबाइल एप्स की मदद से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, मोबाइल फोन पढ़ाई में सहायक होने के साथ-साथ ध्यान भटकाने और सोशल मीडिया की लत का कारण भी बन रहा है। 12वीं के परीक्षा परिणामों में इस बार डिजिटल पढ़ाई का असर साफ दिखाई दिया। कई छात्रों ने ऑनलाइन नोट्स, यूट्यूब लेक्चर और मोबाइल एप्स की मदद से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, मोबाइल फोन पढ़ाई में सहायक होने के साथ-साथ ध्यान भटकाने और सोशल मीडिया की लत का कारण भी बन रहा है। शिक्षा के बदलते दौर में मोबाइल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पढ़ाई का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन वीडियो और क्विक रिवीजन नोट्स से कठिन विषयों को समझना आसान हुआ और तैयारी में समय की बचत हुई। 12वीं के छात्र आयुष झा ने बताया कि ऑनलाइन वीडियो से मैथ्स और फिजिक्स समझने में मदद मिली, जिससे उन्हें 82 प्रतिशत अंक हासिल हुए। हालांकि, नोटिफिकेशन की वजह से कई बार ध्यान भटक जाता था। सिविल लाइंस स्थित बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र कार्तिक ने कहा कि मोबाइल के जरिये रिवीजन आसान हुआ और उन्हें 83 प्रतिशत अंक मिले, लेकिन सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। छात्र निशांत सिंह चौहान के अनुसार डिजिटल नोट्स से समय बचा, मगर लंबे स्क्रीन टाइम से थकान महसूस होती थी।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को पछाड़ा, नतीजों में गिरावट का हो रहा है विश्लेषण

नई दिल्ली (एजेंसी) इस बार भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा। दिल्ली रीजन में सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 94.44 फीसदी दर्ज किया गया जबकि निजी स्कूलों का परिणाम 88.77 फीसदी रहा। दोनों के बीच 5.67 फीसदी का अंतर रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं बोर्ड परीक्षा में दिल्ली रीजन का कुल पास प्रतिशत 91.97 फीसदी रहा। इस बार भी सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा। दिल्ली रीजन में सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 94.44 फीसदी दर्ज किया गया जबकि निजी स्कूलों का परिणाम 88.77 फीसदी रहा। दोनों के बीच 5.67 फीसदी का अंतर रहा। दिल्ली वेस्ट का परिणाम दिल्ली ईस्ट से बेहतर रहा। दिल्ली वेस्ट में 92.34 फीसदी छात्र सफल हुए, जबकि दिल्ली ईस्ट का पास प्रतिशत 91.73 फीसदी रहा। हालांकि दोनों क्षेत्रों के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। बीते साल दिल्ली वेस्ट का पास प्रतिशत 95.37 और दिल्ली ईस्ट का 95.06 फीसदी था। ओवरऑल रैंकिंग में दिल्ली वेस्ट पांचवें और दिल्ली ईस्ट छठे स्थान पर रहे। दिल्ली ईस्ट से 1,84,214 और दिल्ली वेस्ट से 1,21,229 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन और बेहतर रहा था। तब दिल्ली वेस्ट में सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 98.10 और दिल्ली ईस्ट में 96.11 फीसदी था। रिजल्ट में गिरावट का किया जा रहा विश्लेषण देशभर में सीबीएसई का ओवरऑल पास प्रतिशत 85.20 फीसदी रहा, जो पिछले वर्ष के 88.39 फीसदी की तुलना में 3.19 फीसदी कम है। रिजल्ट में गिरावट को ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने इससे इन्कार किया। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हुई है तथा रिजल्ट में गिरावट के कारणों का अभी विश्लेषण किया जा रहा है। पास प्रतिशत में केंद्रीय विद्यालयों ने जवाहर नवोदय को पीछे छोड़ा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारहवीं के नतीजों में केंद्रीय विद्यालयों का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस बार केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का पास प्रतिशत सर्वाधिक 98.55 रहा है। वहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय का पास प्रतिशत 98.47 है। पिछले साल 99.29 फीसदी के साथ जेएनवी स्कूल श्रेणी में पास प्रतिशत के मामले में टॉप पर रहे थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं करने दे सकते, 'गंदगी' हटाओ

नई दिल्ली (एजेंस अदालत ने गूगल, एप्पल और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को निर्देश दिया कि वे ऐसे एप्स के प्रसार को तुरंत रोकें और 2021 के आईटी नियमों का पालन करें। साथ ही, अगली सुनवाई (जुलाई में) तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गूगल और एप्पल को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अश्लील, वेश्यावृत्ति तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मोबाइल एप्लिकेशन्स के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करें। अदालत ने टिप्पणी की कि पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 का हवाला देते हुए कहा कि गूगल और एप्पल जैसे मध्यस्थों की जिम्मेदारी केवल शिकायत मिलने पर ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐप्स को अपलोड होने के समय ही उचित जांच (ड्यू डिलीजेंस) करना है। पीठ ने कहा, इन ऐप्स की व्यापक पहुंच को देखते हुए मध्यस्थों को आईटी नियम 2021 के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें न केवल शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि अपलोड के समय भी सतर्क रहना चाहिए। यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर कई ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जो पोर्नोग्राफिक सामग्री, अनैतिक तस्करी, वेश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध को बढ़ावा देते हैं। याचिकाकर्ता के वकील तन्मय मेहता ने कहा कि ये ऐप्स ऐसे आपराधिक कार्यों से करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले दुनिया भर में सब कुछ ब्लॉक नहीं कर सकती, इसलिए मध्यस्थों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है

एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 10 आरोपियों के खिलाफ 7500 पन्नों में आरोपपत्र

नई दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली के लाल किले इलाके में नवंबर 2025 में हुए कार बम धमाके मामले में एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने 10 नवंबर, 2025 को हुए इस हमले में कथित संलिप्तता के लिए 10 लोगों को नामजद किया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। एनआईए के अनुसार, सहित सभी 10 आरोपी संगठन 'अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे, जिसे अल-कायदा से प्रेरित संगठन बताया गया है। मुख्य आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी। उसके अलावा नौ अन्य आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। डॉ. नबी के अलावा, चार्जशीट में नामित अन्य व्यक्तियों में आमिर राशिद मीर, जसीर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा एनआई की जांच में सामने आया कि कुछ आरोपी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित मेडिकल प्रोफेशनल थे। 2022 में श्रीनगर में हुई एक गुप्त बैठक में उन्होंने AGuH Interim नाम से संगठन को फिर सक्रिय किया और OperationHeavenly Hind शुरू किया था। एनआईए की जांच से पता चला कि OperationHeavenly Hind के तहत, आरोपियों ने नए सदस्यों की भर्ती की, AGuH की हिंसक जिहादी विचारधारा का सक्रिय रूप से प्रचार किया, हथियार और गोला-बारूद जमा किया, और बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर विस्फोटक बनाए। एजेंसी ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल TATP विस्फोटक आरोपियों ने खुद तैयार किया था। एनआईए की जांच से यह भी पता चला कि आरोपी प्रतिबंधित हथियारों की अवैध खरीद में भी शामिल थे, जिनमें एक अङ-47 राइफल, एक क्रिनकोव राइफल और कारतूसों वाली देसी पिस्तौलें शामिल थीं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों ने विभिन्न ऑलाइन और ऑनलाइन स्रोतों से प्रयोगशाला उपकरण खरीदे थे।

स्लीपर बस में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, रात में टाइम बताने के बहाने अंदर खींचा

नई दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली के रानी बाग इलाके में चलती स्लीपर बस में 30 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सरस्वती विहार इलाके में महिला बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक स्लीपर बस आकर वहां रुकी। महिला ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से टाइम पूछा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे बस के अंदर खींच लिया रानीबाग इलाके में सोमवार रात चलती स्लीपर बस में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंगोलपुरी स्थित फैक्टरी में काम करने वाली महिला घटना के समय काम खत्म कर घर जा रही थी। आरोप है कि बस में सवार चालक और हेल्पर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास बस से फेंककर भाग गए। पीड़िता को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बयान पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बस को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, 30 साल की महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ पीतमपुरा इलाके में रहती है। उसके पति को टीबी की बीमारी है। वह मंगोलपुरी स्थित फैक्टरी में काम करती है। रानीबाग थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सोमवार रात वह काम करने के बाद घर जा रही थी। सरस्वती विहार इलाके में वह बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक स्लीपर बस आकर वहां रुकी। महिला ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से टाइम पूछा। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे बस के अंदर खींच लिया और चालक से बस चलाने के लिए कहा। इस दौरान बस में मौजूद दो आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास महिला को बस से फेंककर वहां से भाग गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की, जिसमें पता चला कि बस दिल्ली से बिहार के बीच चलती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बस को जब्त कर आरोपी बस चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।

इन्फ्लुएंसर 'द स्किन डॉक्टर' गिरफ्तार, संजय कपूर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर किए थे आपत्तिजनक पोस्ट

नई दिल्ली (एजेंसी) आरोप है कि इन्फ्लुएंसर ने संजय कपूर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर ₹मानहानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री₹ साझा की थी। आरोपी द्वारा पोस्ट किए गए कुछ ट्वीट आपत्तिजनक प्रकृति के थे और उनसे कपूर परिवार को मानसिक कष्ट पहुंचा। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने कारोबारी संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार को निशाना बनाते हुए कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डमेटोलॉजिस्ट डॉ. नीलम सिंह को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बुधवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कपूर परिवार की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन्फ्लुएंसर ने कपूर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर ₹मानहानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री₹ साझा की थी। पुलिस ने बताया कि डॉ. नीलम सिंह, जिन्हें ऑनलाइन ₹द स्किन डॉक्टर₹ के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है, आरोपों के प्रारंभिक सत्यापन के बाद उन्हें ट्रैक किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांचकर्ता संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं और सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा पोस्ट किए गए कुछ ट्वीट आपत्तिजनक प्रकृति के थे और उनसे परिवार को मानसिक कष्ट पहुंचा। शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। चोरी, मानहानि और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की जांचकर्ता इस बात की भी बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या कोई अतिरिक्त सामग्री अपलोड की गई थी या बाद में उसे हटा दिया गया था। पुलिस इस मामले से संबंधित बयान दर्ज करने और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं। अधिकारी ने कहा कि जांच के हिस्से के रूप में, सामग्री पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा सकती है।

एनडीएमसी में 33 फीसदी कर्मी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू

नई दिल्ली (एजेंसी) एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अनावश्यक आवागमन कम कर ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है। दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी) के 33 फीसदी कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अनावश्यक आवागमन कम कर ईंधन की बचत सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत चिन्हित विभागों के समूह बी और समूह सी के अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी। विभागाध्यक्ष कर्मचारियों की क्रमवार ड्यूटी सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयी कामकाज और जनसेवाएं प्रभावित न हों। दूर-दराज इलाकों से निजी वाहनों के जरिए आने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई है। एनडीएमसी ने स्पष्ट किया कि घर से काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक संचार माध्यमों पर उपलब्ध रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा। वहीं कई जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इनमें सफाई एवं जनस्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल और आपातकालीन सेवाएं, बिजली और जल आपूर्ति कर्मचारी, उद्यान विभाग, अभियांत्रिकी एवं रखरखाव दल, प्रवर्तन और निरीक्षण टीमें तथा नियंत्रण कक्ष और आपदा प्रतिक्रिया कर्मचारी शामिल हैं। एनडीएमसी ने कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। वित्त एवं लेखा विभाग को दिल्ली मेट्रो कार्ड के जरिए यात्रा भत्ता उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अधिकारियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी।

इसके अलावा एनडीएमसी कॉलोनियों से कर्मचारियों के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है।

संक्षिप्त डायरी

नगर निगम में अब हर शनिवार नो फ्यूल डे, नहीं किया जाएगा निजी वाहनों का उपयोग

वाराणसी (एजेंसी) पीएम द्वारा देशवासियों से ईंधन बचत को लेकर की गई अपील के बाद वाराणसी नगर निगम में हर शनिवार ह्यनो फ्यूल डेह्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। निगम ने ईंधन बचत में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कदम उठाया है। मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर निगम के पार्षदों ने निर्णय लिया है कि अब नगर निगम के जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन यानी हर शनिवार को पेट्रोल या डीजल से चलने वाले निजी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। अर्थात शनिवार को नो फ्यूल डे के रूप में मनाया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय स्थित महापौर कक्ष में बुधवार को पार्षदों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। इस दौरान तय हुआ कि हर शनिवार को सभी पार्षद अपने घर से निगम कार्यालय तक आने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करेंगे। बैठक के दौरान मेयर ने स्वयं उदाहरण पेश करते हुए घोषणा की कि जब तक तेल का संकट बना हुआ है, तब तक वह अपने घर से नगर निगम कार्यालय तक का सफर पैदल ही तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। इसी क्रम में निगम ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कदम उठाया है। हालांकि, कूड़ा गाड़ियों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है, क्योंकि निगम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है। महापौर ने निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे राष्ट्रहित में सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग न करें।

बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्रकैद, तीन साल बाद आया फैसला; जानें- पूरा मामला

वाराणसी (एजेंसी) जिले के कैंट थाना क्षेत्र की घटना है। तीन वर्ष पूर्व कैंट थाने में पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरूआत में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में छानबीन करने पर दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आई थी। मामले में तीन साल बाद फैसला आया है। वाराणसी कैंट थाना क्षेत्र में करीब 12 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने फुलवरिया (कैंट) निवासी अभियुक्त सनोज उर्फ राहुल को दोषी पाते हुए 62 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने घटना से जुड़े पुख्ता साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी लगभग 12 वर्षीय पुत्री 1 मार्च 2023 की सुबह करीब 10 बजे घर के बाहर खेलने निकली थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने शुरूआत में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमों ने जांच शुरू की। विवेचना के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने फुलवरिया निवासी सनोज उर्फ राहुल को हिरासत में लिया। पूछताछ और साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त ने बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद, पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया।

डंपर चालकों ने कंपनी कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप, काम बंद कर हड़ताल पर बैठे

कानपुर (एजेंसी) महाराजपुर में रिंग रोड निर्माण में लगे डंपर चालकों ने कंपनी कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाकर बुधवार शाम से काम ठप कर दिया है। पुलिस कानपुर में उन्नाव से चकेरी आ रही रिंग रोड में लगे डंपर चालकों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए बुधवार शाम से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि कंपनी में ही कार्यरत कर्मचारियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है और विरोध पर बाहरी लोगों को बुलाकर जान से मारने का प्रयास किया है। मूलरूप से सोनभद्र के ग्राम व पोस्ट कोटा के रहने वाले शिवकुमार और फतेहपुर भरसवा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि एचसीसी कंपनी कानपुर चकेरी में रिंग रोड बना रही है। इसका प्लांट महाराजपुर के रूमा स्थित सलेमपुर के पास बनाया गया है। गाली गलौज के साथ मारपीट भी की चालकों का आरोप है कि बुधवार शाम कंपनी के ही निरंजन, राजू व राममूरत द्वारा गाली गलौज की गई। इसका विरोध करने पर बुरी तरह से हम लोगों के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद आरोपियों ने फिर से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित शिव कुमार ने बताया कि वह दूसरे जिले का रहने वाला है। ऐसे में इन आरोपियों द्वारा कोई भी घटना की जा सकती है। इसलिए वह काम नहीं करना चाहते, लेकिन कंपनी द्वारा उसका हिसाब भी नहीं किया जा रहा है। मामले में महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

सराफा में ब्रेकडाउन जैसा हाल, आयात शुल्क बढ़ने से सोना-चांदी महंगे, 54 करोड़ का कारोबार अब चार करोड़

मेरठ (एजेंसी) सरका र द्वारा सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने के बाद मेरठ के सराफ बाजार में मंदी छा गई है। रोजाना 54 करोड़ रुपये का कारोबार घटकर चार करोड़ पर पहुंच गया है और करीब 20 हजार कारीगरों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। सरकार ने सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इससे सोना मंडी सर्वाधिक प्रभावित हुई है। 54 करोड़ के प्रतिदिन का कारोबार दो दिन में ही चार करोड़ पर सिमट गया है। बाजार में सोने की कीमत बढ़ने के कारण पुराने आभूषण भी नहीं आ रहे हैं। बीटूबी यानी बायर टू बायर और बीटूसी यानी बायर से खरीदार सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। इस बीच कम कैरेट वाले आभूषण और गोटा चांदी का कारोबार रफ्तार पकड़ रहा है। सोना मंडी में बुधवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 1 .58 लाख, 100 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2 .77 लाख रुपये प्रति किलो रही। मंगलवार को सोने की कीमत बढ़कर 1 .52 लाख, 100 रुपये और चांदी की कीमत 2 .62 लाख, 500 रुपये प्रति किलो पहुंची थी। आयात शुल्क लागत बढ़ने से घरेलू बाजार में सोने की खुदरा कीमतों पर सीधा असर पड़ा है। इससे पूर्व सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में घरेलू रत्न एवं आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने, अवैध तस्करी पर रोक लगाने और स्थानीय बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सोने पर आयात शुल्क घटाकर छह प्रतिशत किया था।

यूपी में कुदरत का कहर: 89 मौतें, सीएम योगी का युद्धस्तर पर राहत और मुआवजे का आदेश

लखनऊ (एजेंसी) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद पहुँचाने का आदेश दिया है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 13 मई को तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसी खराब मौसम की स्थितियों के कारण पूरे राज्य में 89 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी कुदरत के कहर ने भारी तबाही मचाई है। धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं में अब तक 89 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद पहुँचाने का आदेश दिया है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 13 मई को तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसी खराब मौसम की स्थितियों के कारण पूरे राज्य में 89 लोगों की मौत हुई, 53 लोग घायल हुए, 114 मवेशियों की जान गई और 87 घरों को नुकसान पहुँचा। प्रयागराज, भदोही, कानपुर देहात और फतेहपुर जैसे ज़िलों से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें मिलीं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को तत्काल तेज करें। उट योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि पीड़ितों के प्रति किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तूफान और भारी बारिश से प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे तत्काल जान-माल और संपत्ति के नुकसान का आकलन करें, और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा वितरित कर दिया जाए। उट योगी द्वारा जारी निदेशों के बाद, राहत आयुक्त कार्यालय सभी ज़िलों में स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। इस बीच, प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वे चल रहे बचाव कार्यों की देखरेख के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रभावित स्थलों का दौरा करें। योगी सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पीड़ित परिवार तक राहत पहुँचाने में कोई देरी न हो। इसके अलावा, बिजली गिरने और तेज तूफान के कारण कई क्षेत्रों में घरों, फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुँचा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, और जनता से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है। सरकार का कहना है कि बचाव और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता जल्द से जल्द पहुँच सके।

नाबालिग छात्रा को दिया जहर, प्रेमी सहित तीन पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

अलीगढ़ (एजेंसी) प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए मोबाइल कॉल डिटेल्स और मेसेज खंगाले जा रहे हैं। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को नाबालिग छात्रा (17) को धोखे से जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मृतका के कथित प्रेमी और उसके दो साथियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। इस संबंध में छात्रा के पिता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि छात्रा के फोन पर मुख्य आरोपी का मेसेज आया था कि वह अपने साथियों के साथ अलीगढ़ आया हुआ है और कुछ जरूरी बात करना चाहता है। इसके बाद वह अपने दो साथियों के साथ घर पहुंचे। उस वक्त छात्रा घर पर अकेली थी। आरोपियों ने उसे एक पुड़िया देते हुए कहा कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद दवा है और इसे तुरंत खा ले। कुछ देर बाद आरोपियों ने दोबारा फोन किया और पूछा कि क्या उसे नींद आ रही है ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। शाम को जब छात्रा का भाई घर पहुंचा तो उसने छात्रा की हालत बिगड़ती देखी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। छात्रा के कमरे से पुलिस को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पुड़िया बरामद हुई है। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस के उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप और एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। शाम को पुलिस सुरक्षा के बीच छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए मोबाइल कॉल डिटेल्स और मेसेज खंगाले जा रहे हैं। सीओ गभाना महेश चंद्र ने बताया कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं।यह आत्महत्या के लिए

सोने-चांदी के दाम में अचानक उछाल, मुरादाबाद के स्टोरों में छाई वीरानी, सहालग सीजन में भी कारोबार ठंडा

मुरादाबाद (एजेंसी) सोने और चांदी के दाम में अचानक उछाल आने से कारोबारी ठंडा पड़ गया है। मुरादाबाद के कई स्टोरों में ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि शादी का सीजन होने के बाद भी कोई खरीदार नहीं आ रहा है। शादियों के सीजन (सहालग) के बीच सोने-चांदी की कीमतों में आए उछाल ने बाजार की रौनक छीन ली। बुधवार को गंज बाजार व मंडी चौक स्थित सराफा बाजार में गिने-चुने ग्राहक सोने व चांदी की खरीदारी करते दिखाई दिए। दो दिनों में सोने की कीमतों में सात हजार रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम में 20 हजार रुपये प्रतिकिलो की भारी बढ़ोतरी हुई है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि एकाएक सोने व चांदी पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी से गहनों की बिक्री पर असर देखने को मिला है। उनका कहना है कि लोग हल्के गहनों (लाइट वेट ज्वैलरी) खरीदना पसंद कर रहे थे। अब मौजूदा कीमतों पर हल्के गहने बनवाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सोने व चांदी पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। ड्यूटी बढ़ने से विदेशों में सोना व चांदी महंगा हो गया। इसका सीधा बोझ अब ग्राहकों पर पड़ेगा। गंज बाजार स्थित सराफा कारोबारियों के दुकानों पर सहालग में पैर रखने की जगह नहीं होती थी लेकिन अब वहां केवल दुकानदार और काम करने वाले कर्मचारी नजर आए। सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोने व चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं थी। शादियों में गहने खरीदने के लिए लोग पहले से बजट तय कर रखते हैं। लेकिन दो दिनों के अंदर में सोने व चांदी के दाम बढ़ने से अब गहने खरीदना काफी मुश्किल हो जाएगा। सराफा कारोबारी बताते हैं कि पहले से ही सोने व चांदी के दाम बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से हल्के गहने बनाए जा रहे थे लेकिन अब सोने व चांदी कीमतें और बढ़ गई हैं। इससे ग्राहकों के लिए हल्के गहने बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर सोने व चांदी की कीमतें जल्द ही स्थिर नहीं हुई तो इस सीजन में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दुकान पर सुबह से खाली बैठा हूं। एक भी ग्राहक नहीं आया। आयात शुल्क में बढ़ोतरी से सोन व चांदी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसके लगता है कि आने वाले दिनों में ग्राहक बिल्कुल ही नहीं आएंगे। -नीरज अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री सराफा कमेटी ग्राहकों के बजट के हिसाब से बाजार में हल्के गहने बना दिए गए हैं। अब सोने व चांदी की बढ़ी कीमतों ने बिक्री की चिंता और बढ़ा दी है। बाजार में ग्राहक नहीं है। मेरे पास आज एक भी ग्राहक नहीं आया।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव, ट्रक में जा घुसी स्कार्पियो, एक ही परिवार के चार की मौत

बुंदेलखंड (एजेंसी) एक्सप्रेसवे पर एक स्कार्पियो गाड़ी सिलिंडर लदे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में आजमगढ़ निवासी एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल युवती को कानपुर रेफर किया गया है। बांदा जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें एक स्कॉर्पियो गैस सिलिंडर लदे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में स्कॉर्पियो के चालक सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, एक 20 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती को कानपुर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सभी मृतक और घायल आजमगढ़ के रामगढ़ के रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो कबरई जा रहे थे। डीएम अमित आसेरी ने दिए निर्देश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी अमित आसेरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक स्कार्पियो और ट्रक की भिड़ंत हुई है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। एक युवती गंभीर रूप से घायल प्रशासन द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना में एक युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। प्रशासन पीड़ित परिवार के संपर्क में है और नियमानुसार हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। नींद की झपकी बनी चार मौतों का कारण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हादसे को लेकर एसपी पलाश बंसल ने बताया कि आज थाना कोतवाली देहात को सूचना मिली कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक डीसीएम और स्कार्पियो के बीच भिड़ंत हो गई है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। गाड़ी पीछे से डीसीएम में जा घुसी स्कार्पियो में एक पुरुष और चार महिलाएं सवार थीं। मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण स्कार्पियो चालक को नींद की झपकी आना प्रतीत हो रहा है, जिससे

अस्पताल बना मंडप, आईसीयू में भरी मांग, फेरों से पहले निभा दिया वचन; इसलिए दुल्हन को कराना पड़ा था भर्ती

गोरखपुर (एजेंसी) गोरखपुर में शादी के दिन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर दुल्हन को आईसीयू में भर्ती कराया गया। दुल्हन के दरवाजे पर द्वारपूजा और अन्य रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा अस्पताल पहुंचा सात जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। दूल्हे ने आईसीयू में युवती की मांग भरी। बदकिस्मती भरे एक हादसे से मद्धम पड़ती खुशियों की रौनक को दो परिवारों की आपसी समझ और जज्बातों ने नई रंगत दे दी। शादी के दिन हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आईसीयू में पड़ी दुल्हन की मांग भावनाओं के सिंदूर से सजाकर दूल्हे ने एक नई मिसाल पेश की। बांसगांव के हटवार गांव की रहने वाली पूजा यादव का रिश्ता परिवार के लोगों ने महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से तय किया था। नवंबर 2025 में यह रिश्ता तय होने के बाद 13 मई को शादी के लिए पूजा के घर बरात आनी थी। घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। नई जिंदगी के सपने संजोए पूजा एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की अपनी परीक्षा देने भाई के साथ खलीलाबाद स्थित कॉलेज के लिए निकली तो परिवार की महिलाओं ने हंसी-ठिठोली करते हुए बलाएं उतारी थीं। बदकिस्मती भरे एक हादसे से मद्धम पड़ती खुशियों की रौनक को दो परिवारों की आपसी समझ और जज्बातों ने नई रंगत दे दी। शादी के दिन हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आईसीयू में पड़ी दुल्हन की मांग भावनाओं के सिंदूर से सजाकर दूल्हे ने एक नई मिसाल पेश की। बुधवार को दुल्हन के दरवाजे पर द्वारपूजा और अन्य रस्में पूरी करने के बाद दूल्हा अस्पताल पहुंचा सात जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। बांसगांव के हटवार गांव की रहने वाली पूजा यादव का रिश्ता परिवार के लोगों ने महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव से तय किया था। नवंबर 2025 में यह रिश्ता तय होने के बाद 13 मई को शादी के लिए पूजा के घर बरात आनी थी। घर में मंगल गीत गूंज रहे थे। नई जिंदगी के सपने संजोए पूजा एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की अपनी परीक्षा देने भाई के साथ खलीलाबाद स्थित कॉलेज के लिए निकली तो परिवार की महिलाओं ने हंसी-ठिठोली करते हुए बलाएं उतारी थीं। छलकती आंखों से बरसीं दुआएं शाम को सन्नी यादव बरात लेकर हटवार गांव पहुंचे। वहां द्वारपूजा और अन्य प्रारंभिक रस्में पूरी की गईं। इसके बाद तय हुआ कि दूल्हा अस्पताल जाकर सिंदूरदान करेगा।

यूपी में आंधी-तूफान से 96 की मौत, भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की गई जान

लखनऊ (एजेंसी) यूपी में आंधी-तूफान से भदोही में 18, मिजार्पुर में 15, प्रयागराज में 17, प्रतापगढ़ और बरेली में 4-4, फतेहपुर में 10, उन्नाव और बदायूं में 6-6, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में दो-दो, कौशांबी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुरखीरी में एक-एक मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी-पानी की चपेट में आने से अलग-अलग जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। मरने वालों में भदोही में 18, मिजार्पुर में 15, प्रयागराज में 17, प्रतापगढ़ और बरेली में 4-4, फतेहपुर में 10, उन्नाव और बदायूं में 6-6, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में दो-दो, कौशांबी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुरखीरी में एक-एक लोग शामिल हैं। प्रतीक की मौतः किचन में सुबह चार बजे अचेत पड़े मिले, नौकर ने यहां लगाया फोन; घर पर नहीं थीं पत्नी अपर्णा; एक क्लिक में पूरी कहानी सीएम ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने का दिया निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए। सीएम ने मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांदा रहा प्रदेश में सर्वाधिक गर्म प्रदेश में एक ओर जहां आंधी बारिश से नुकसान के अलावा गर्मी से कुछ राहत मिली, वहीं बुंदेलखंड समेत दक्षिणी जिलों में तेज धूप और भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। बांदा 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा झांसी में 44.5, प्रयागराज में 43.5, हमीरपुर में 43.2 और उरई में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बृहस्पतिवार से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी आंधी की वजह से दिल्ली-हावड़ा रूट करीब डेढ़ घंटे के लिए बाधित हो गया। फतेहपुर में पेड़ गिरने से ओएचई लाइन टूट गई। इससे कानपुर होकर आने-जाने वाली करीब 22 ट्रेनें प्रभावित हुई। शाम छह बजे ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। प्रयागराज-जौनपुर रेल खंड पर थरवई और सरायचंडी रेलवे स्टेशन के बीच गेट नंबर आठ-सी पर एक भारी-भरकम पेड़ अप और डाउन दोनों रेल लाइनों पर गिर गया,

संक्षिप्त समाचार

हंगरी में 16 साल बाद नई सरकार, मंत्रियों ने संभाले पदभार

बुडापेस्ट, एजेंसी। यूरोपीय देश हंगरी में 16 साल के बाद व्यवस्था बदल गई है। मंत्रियों ने पदभार संभाल लिए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मंगलवार को प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल मंत्रियो को शपथ दिलाई गई। सत्ता हस्तांतरण से पहले मैग्यार की प्रो-यूरोपीय तिस्ज़ा पार्टी ने पिछले महीने ओर्बन की फ़िडेज़ पार्टी को हराकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। इसी के साथ 16 साल से चला आ रहा ओर्बन के राजनीतिक सिस्टम का पटाक्षेप हो गया है। पीटर मैग्यार ने अपनी नीतियों का संकेत देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली नई सरकार सभी हंगरीवासियों की होगी और मंत्री राष्ट्र सेवा की भावना के साथ काम करेंगे। मैग्यार ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सार्वजनिक धन की वसूली, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने जैसे लुभावने वादे भी किए। नई सरकार में 16 मंत्रालय हैं, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के लिए अलग विभाग हैं। इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के जमे हुए करीब 17 अरब यूरो के फंड को वापस लाना है, जिस पर विदेश मंत्री अनीता ओर्बन ने भी जोर दिया।

मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर हार्मोन का निधन

न्यूयार्क, एजेंसी। वन लाइफ टु लिव और हाउ टु सरवाइव ए मैरिज जैसे लोकप्रिय सोप ओपेरा के लिए मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर हार्मोन का निधन हो गया है। वह 82 साल की थीं। परिजनों ने बताया कि जेनिफर ने शनिवार को न्यूयॉर्क में आखिरी सांस ली। हार्मोन ने अपने लगभग पांच दशकों के करिअर में ब्रॉडवे मंच (थिएटर) पर 21 बार अपनी कला का प्रदर्शन कर विशिष्ट पहचान बनाई थी। वे रंगमंच की दुनिया का एक प्रतिष्ठित चेहरा थीं। जेनिफर हार्मोन लोकप्रिय टीवी शो 'वन लाइफ टू लिव' में 'कैथी' का किरदार निभाने के लिए जानी जाती थीं। वह इस भूमिका को निभाने वाली पांचवीं अभिनेत्री थीं। उन्होंने 1976 से 1978 तक यह रोल किया और इसके लिए डे-टाइम एमी अवॉर्ड के लिए नामांकन भी मिला था। इससे पहले उन्होंने 1974-75 में ह्वष्ट के शो 'हाउ टू सरवाइव ए मैरिज' में मुख्य भूमिका में नजर आई थीं। जेनिफर हार्मोन का जन्म 3 दिसंबर 1943 को कैलिफोर्निया के पासाडेना में हुआ था। वह न्यू ऑरलियन्स में बड़ी हुईं। उन्होंने मिसिसिपी और मिशिगन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। इसके बाद न्यूयॉर्क जाकर उन्होंने थिएटर में काम शुरू किया। 1965 में जेनिफर ने ब्रॉडवे पर डेब्यू किया। उनके करियर में 'द स्कूल फॉर स्कैंडल', 'ब्लाइथ स्पिरिट', 'द ग्लास मेनेजरी', 'बेयरफुट इन द पार्क' जैसे कई प्रसिद्ध सीरियल्स में काम किया है। उन्होंने कई दशकों तक ब्रॉडवे पर अपनी अच्छे अभिनय का लोहा मनवाया। 'वन लाइफ टू लिव' में 1990 के दशक में वह एक वकील के रोल में भी वापस लौटी थीं। उन्होंने 'अनदर वर्ल्ड', 'गाइडिंग लाइट' और 'लविंग' जैसे कई सोप ओपेरा में भी काम किया।

एक और पर्वतारोही की माउंट एवरेस्ट पर मौत, अब तक 3 मरे

काठमांडू, एजेंसी। माउंट एवरेस्ट पर एक और नेपाली पर्वतारोही की दरार में गिरने से मौत हो गई। पिछले दो हफ्तों के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर होने वाली यह तीसरी मौत है। अधिकारियों ने बताया कि 21 वर्षीय फुरा ग्यालजेन शेरपा कैंप-3 के पास बर्फ पर फिसलकर लगभग 7,200 मीटर की ऊंचाई पर हादसे का शिकार हुए। इससे पहले खूंबू आइसफॉल और बेस कैंप के रास्ते में दो अन्य नेपाली पर्वतारोहियों बिजय घिमिरे बिश्वकर्मा (35) और लक्पा देंडी शेरपा (51) की जान गई थी।

आईडीएमसी रिपोर्ट में खुलासा : युद्ध और हिंसा ने दुनिया में मचाई तबाही, अपने ही देश में बेघर हुए 8.2 करोड़ लोग

जिनेवा, एजेंसी। दुनियाभर में संघर्ष, गृहयुद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और जलवायु आपदाओं ने करोड़ों लोगों को अपने ही देश में बेघर कर दिया है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (आईडीएमसी) व नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (एनआरसी) की ताजा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2026 के अनुसार 2025 के अंत तक 104 देशों में 8 करोड़ 22 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित जीवन जी रहे थे। यह संख्या जर्मनी की आबादी के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में यह आंकड़ा दोगुने से अधिक हो गया है और पहली बार युद्ध तथा हिंसा ने प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ 22 लाख विस्थापितों में 6 करोड़ 86 लाख लोग संघर्ष और हिंसा के कारण बेघर हुए। रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में इस्त्राइल और ईरान के बीच हुए 12 दिन के संघर्ष ने आधुनिक समय की सबसे बड़ी एकल आंतरिक विस्थापन घटना पैदा की। इस्त्राइली सैन्य कार्रवाई और निकासी चेतावनियों के बाद तेहरान से करीब एक करोड़ लोगों को भागना पड़ा।

डेमोक्रेटिक नेताओं ने दी ईरान में बढ़े पैमाने पर युद्ध बढ़ने की चेतावनी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सीनेटरों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका को मध्य पूर्व में एक और लंबे युद्ध की तरफ धकेल सकता है। ईरान के साथ चल रहे तनाव और युद्ध को लेकर अमेरिकी सीनेट में हुई एक अहम सुनवाई के दौरान नेताओं के बीच गहरे मतभेद सामने आए। इस दौरान युद्ध की बढ़ती आर्थिक और सैन्य लागत पर भी चिंता जताई गई। यह बहस उस समय हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट प्रस्ताव पर सीनेट की रक्षा संबंधी उपसमिति में चर्चा चल रही थी। कई डेमोक्रेट सीनेटर्स ने मौजूदा हालात की तुलना अमेरिका के पुराने इराक और अफगानिस्तान युद्धों से की। उनका कहना था कि सरकार के पास इस संघर्ष को खत्म करने की कोई स्पष्ट और लंबी रणनीति दिखाई नहीं दे रही है। सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि प्रशासन किसी व्यापक राजनीतिक योजना के बिना, युद्ध के मैदान में मिलने वाली छोटी-मोटी जीतों पर ही केंद्रित लग रहा है। कून्स ने कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पहले एक आम सहमति हुआ करती थी कि अमेरिका को युद्ध में तभी उतरना

चाहिए जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा हो, जब बाकी सभी विकल्प खत्म हो चुके हों, और जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य और यह योजना हो कि युद्ध का अंत कैसे होगा।' कून्स ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बार-बार यह सवाल किया कि प्रशासन अब तक होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं बना पाया। इस समुद्री रास्ते पर ईरान के दबाव की वजह से दुनियाभर में तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ सैन्य सफलताएं जरूर मिली हैं, लेकिन रणनीतिक स्तर पर अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सीनेटर क्रिस्टोफर मर्फी ने भी सवाल उठाया कि क्या प्रशासन ईरान की, लंबे समय तक आर्थिक और सैन्य दबाव झेलने की क्षमता को कम करके आंक रहा है। मर्फी ने कहा, 'यह एक बहुत जोखिम भरी रणनीति है।' उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान तो शायद वर्षों तक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव को झेल जाए, लेकिन अमेरिकी परिवारों को ईंधन की आसमान छूती कीमतों के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

मर्फी ने तर्क दिया कि 'इस मामले में समय हमारे पक्ष में नहीं है,' क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें पहले से ही अमेरिकी किसानों और आम परिवारों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

सीनेटर पैटी मरे ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घरेलू जरूरतों से ज्यादा युद्ध पर पैसा खर्च कर रही है। मरे ने कहा, 'आप परिवारों की गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स के पैसों को एक ऐसे युद्ध पर खर्च कर रहे हैं जिसका बहुत से लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आप अगले साल के लिए युद्ध के बजट में आधा ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। डेमोक्रेट नेताओं ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए सरकार के पास कानूनी अधिकार हैं या नहीं। उनका कहना था कि इतने बड़े संघर्ष के लिए कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी जरूरी होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्री हेगसेथ ने ट्रंप प्रशासन का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने वह हासिल किया है जो पिछली सरकारें नहीं कर सकीं। उनका कहना था कि अमेरिका के पास पहले से ज्यादा दबाव बनाने की ताकत है और यह अभियान ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी है। पेंटागन अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान संघर्ष पर करीब 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। सीनटरों ने चेतावनी दी कि अगर सैन्य अभियान लंबे समय तक जारी रहा और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को और नुकसान हुआ, तो यह खर्च और तेजी से बढ़ सकता है।

पूरी बहस से यह साफ दिखाई दिया कि वॉशिंगटन में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि ईरान के साथ यह टकराव आगे चलकर एक बड़े और लंबे युद्ध में बदल सकता है। ठीक ऐसे समय में अमेरिका पहले ही चीन, रूस और यूक्रेन से जुड़े मामलों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

नहीं डालेंगे हथियार, इजरायल के लिए बना देंगे नरक; हिजबुल्लाह प्रमुख ने दी सीधी धमकी

तेहरान, एजेंसी। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता नईम कासिम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समूह की सैन्य क्षमताएं और हथियार पूरी तरह से लेबनान का आंतरिक मामला हैं। इजराइल के साथ चल रही शत्रुता के दौरान इन्हें किसी भी सौदेबाजी की मेज पर नहीं रखा जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, कासिम ने टेलीविजन संबोधन में इजरायली सैन्य दबाव का मुकाबला करते हुए कहा कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। हम इजरायल के लिए इसे नरक बना देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लड़ाके लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इस दौरान कासिम ने लेबनानी सरकार के साथ भविष्य के सहयोग की रूपरेखा भी पेश की, जिसमें पांच प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं... इजरायली आक्रामकता समाप्त कर लेबनान की संप्रभुता सुनिश्चित करना कब्जे वाले सभी क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी

बंदियों की रिहाई : विस्थापित नागरिकों की दक्षिणी लेबनान में सुरक्षित वापसी व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य वहीं, विदेशी हस्तक्षेप पर कासिम ने कहा कि लेबनान के बाहर किसी भी देश या पक्ष को हथियारों, प्रतिरोध आंदोलन या आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हिजबुल्लाह प्रमुख ने साफ किया कि प्रतिरोध के हथियार अंतरराष्ट्रीय वार्ताकारों के लिए चर्चा का विषय नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह लेबनान का आंतरिक मामला है और दुश्मन के साथ किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। नईम कासिम ने आगे बताया कि पांच बिंदुओं को हासिल करने के बाद लेबनान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत आंतरिक मामलों को व्यवस्थित करेगा, जिसमें प्रतिरोध आंदोलन सहित अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब लेबनान-इजरायल सीमा पर अस्थिरता बरकरार है। मई 2026 के मध्य तक अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ युद्धविराम, जो मूल रूप से 17 अप्रैल को लागू हुआ था, अब कागजी घोषणा बनकर रह गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के बफर जोन में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और रोजाना झड़पें जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च से अब तक इजरायली बलों ने लेबनान के लगभग 6 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि 2 मार्च को संघर्ष बढ़ने के बाद स्थिति बेहद खराब हो गई है। अल जजीरा के अनुसार, इजरायली अभियानों में 2840 से अधिक लोग मारे गए और 8700 से ज्यादा घायल हुए हैं। एक लाख से अधिक नागरिक विस्थापित हो चुके हैं।

धमाके से दहला पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत, कई घायल

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में हुए ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि यह ब्लास्ट नौरंग बाजार में हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा का काफी व्यस्त कारोबारी केंद्र माना जाता है।

आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया : प्राथमिक सूचना के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था। हमलावर विस्फटकों से लैस एक ऑटो रिक्शा में सवार हो कर भीड़ भरे बाजार में पहुंचा और धमाका कर दिया। इस ब्लास्ट में दो सुरक्षा अधिकारी समेत 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हो गए। यह घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले में हुई। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आत्मघाती हमलावर ने नौरंग बाज़ार के फाटक चौक पर विस्फोटकों से भरे अपने ऑटो रिक्शा में धमाका कर दिया।

मृतकों में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल : अधिकारियों ने बताया कि इस ब्लास्ट में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सराय नौरंग स्थित तहसील मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त यह आत्मघाती हमला हुआ उस वक्त बाजार में काफी भीड़-भाड़ थी। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आगे के इलाज के लिए बन्नू और पेशावर के अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। घायलों की तादाद को देखते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और सभी मेडिकल स्टाफ को बुला लिया गया है। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता शाहदाब खान ने बताया कि ब्लास्ट की सूचना मिलते ही राहत कार्यों के लिए घटनास्थल पर एंबुलेंस और टीमें भेजी गईं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सुहैल अफरीदी ने इस ब्लास्ट का संज्ञान लिया और पुलिस महानिरीक्षक को घटना पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 'इस मुश्किल समय में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, और प्रांतीय सरकार उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराएगी।

अर्जेंटीना: राष्ट्रपति मिलेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग

ब्यूनस आयर्स, एजेंसी। अर्जेंटीना में मंगलवार को हजारों लोग देशभर के बड़े शहरों की सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की ओर से सरकारी विश्वविद्यालयों की फंडिंग में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संकटग्रस्त देश में सरकारी विश्वविद्यालय व्यवस्था लोगों के लिए गर्व का विषय मानी जाती है। राजधानी ब्यूनस आयर्स में भारी भीड़ ने सरकारी मुख्यालय तक रैली निकाली और विश्वविद्यालयों के बजट में कमी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि फंड की कमी से देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। अर्जेंटीना की सरकारी विश्वविद्यालय व्यवस्था देश के शिक्षित कार्यबल की मजबूत नींव मानी जाती है और मध्यम वर्ग के लिए यह गर्व की बात है। यहां 1949 से पढ़ाई मुफ्त है और इसी व्यवस्था ने पांच नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। पिछले साल संसद ने विश्वविद्यालयों के खर्च और शिक्षकों के वेतन को बढ़ती महंगाई के हिसाब से बढ़ाने के लिए कानून पारित किया था। लेकिन सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया और अदालत में इस कानून को चुनौती दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह मिलेई भी अक्सर विश्वविद्यालय परिसरों को 'वोक विचारधारा' फैलाने वाली जगह बताते हैं। मिलेई ने सरकारी खर्च में भारी कटौती की अपनी योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र की फंडिंग कम कर दी है। उनका कहना है कि पिछली वामपंथी सरकारों ने लापरवाही से खर्च किया, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा। मंगलवार के प्रदर्शन में हर उम्र और अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग शामिल हुए। यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है, जब आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, कम होती तनख्वाह और बढ़ती बेरोजगारी के कारण मिलेई की लोकप्रियता घट रही है। हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के कई मामलों ने भी सरकार को घेरा है। खास तौर पर कैबिनेट प्रमुख मैनुअल अडोर्नी के कथित खर्चों की जांच चर्चा में है। आरोप है कि उनका खर्च उनकी सरकारी तनख्वाह और घोषित संपत्ति से मेल नहीं खाता। एक छात्र के पोस्टर पर लिखा था, अडोर्नी पर हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है? विश्वविद्यालय मामलों के उप सचिव अलेजांद्रो अल्वारेज ने मंगलवार के प्रदर्शन को 'पूरी तरह राजनीतिक' बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों के बढ़े हुए खर्च के लिए अतिरिक्त पैसा दिया है। लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताया है। सरकार का कहना है कि जिस कानून को चुनौती दी गई है, उसमें यह स्पष्ट नहीं बताया गया अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने देश की सर्वोच्च अदालत से 'जनता की आवाज सुनने' की अपील की। मुख्य शिक्षक संघ के अनुसार, 2023 के आखिर में मिलेई के सत्ता में आने के बाद महंगाई को देखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षकों की वास्तविक आय में करीब 33 फीसदी की गिरावट आई है। ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के कुलपति रिकार्डो गेल्पी ने कहा कि खरीदने की क्षमता घटने के कारण इंजीनियरिंग और विज्ञान विभाग के कम से कम 580 शोध प्रोफेसरों ने सरकारी संस्थान छोड़ दिए हैं।

अमेरिका में एफडीए प्रमुख डॉ मकरी का इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक संस्था एफडीए के कमिश्नर डॉक्टर मार्टी मकरी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले काफी समय से प्रशासन के भीतर और बाहर से उन पर दबाव बनाया जा रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी पुष्टि की। ट्रंप ने मकरी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक कठोर परिश्रमी डॉक्टर बताया। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप उन्हें बर्खास्त करने की योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके थे। अब उनकी जगह काइल डायमांटास कार्यकारी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे।

फ्लेवर्ड ई-सिगरेट पर छिड़ा था 'शीत युद्ध' : डॉक्टर मकरी के इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह ई-सिगरेट नीति को माना जा रहा है। पिछले सप्ताह एफडीए ने पहली बार फ्रूट-फ्लेवर्ड ई-सिगरेट को बाजार में उतारने की मंजूरी दी थी। मकरी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि फलों के स्वाद वाले वेप्स बच्चों और युवाओं को नशे की लत में धकेल देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इसी वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। प्रशासन के अन्य अधिकारी इस मंजूरी के पक्ष में थे, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

आंतरिक कलह के बाद शीर्ष अधिकारियों का पलायन : मकरी का एक साल का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। उनके नेतृत्व में एफडीए के भीतर भारी अस्थिरता देखी गई। एजेंसी के लगभग सभी वरिष्ठ करियर अधिकारियों ने या तो इस्तीफा दिया या उन्हें हटा दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर के हस्तक्षेप और राजनीतिक हितों के कारण वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझौते के आरोप लगे। ड्रग सेंटर में एक साल के भीतर छह अलग-अलग निदेशक बदले गए। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर गया और एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

फार्मा दिग्गज और एक्टिविस्ट भी थे नाराज : डॉक्टर मकरी को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। फार्मा कंपनियों के सीईओ उनकी नीतियों से असंतुष्ट थे। उनका आरोप था कि मकरी की कार्यशैली से दवाओं की मंजूरी में अनिश्चितता पैदा हुई है। दूसरी ओर, गर्भपात विरोधी समूह भी उन पर हमलावर थे। इन समूहों का आरोप था कि मकरी गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन की समीक्षा में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। वहीं, वेपिंग लॉबिस्टों ने ट्रंप से शिकायत की थी कि मकरी उनके उत्पादों के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं।

अधर में लटकीं मकरी की नई योजनाएं : मकरी ने दवा समीक्षा प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई पहल की थीं। उन्होंने इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर जोर दिया था। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद इन योजनाओं का भविष्य धुंधला गया है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों को अभी तक कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में नए प्रमुख इन फैसलों को आसानी से पलट सकते हैं। विपक्षी दल भी इन योजनाओं की वैधता पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं।

ईरान पर नई मुसीबत, अमेरिका से तनाव के बीच भूकंप से दहली राजधानी तेहरान

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका के साथ युद्ध के बीच ईरान पर नई मुसीबत आ गई है। खबर है कि मंगलवार को राजधानी तेहरान में भूकंप आया है। इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। हालांकि, इस दौरान किसी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल, मुल्क के कई शहरों में राहत टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले 3 मार्च को भी ईरान के गेराश क्षेत्र में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.3 रही थी। आईआरआईबी यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार, भूकंप के एक घंटे के बाद तक भी नुकसान की कोई खबर नहीं थी। साथ ही कहा गया है कि इस दौरान किसी तरह का आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ है। एजेंसी ने लिखा, 'तेहरान, माजनदरान, कोम और अलबोर्ज में रेड क्रीसेंट फोर्सेज को अलर्ट पर रखा गया है।' शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी नीचे तेहरान-माजनदरान प्रांत सीमा के पास था। यह राजधानी तेहरान से 41 किमी और करज से 77 किमी दूरी पर है। भूकंप के झटके तेहरान प्रांत के पूर्वी हिस्सों और माजनदरान प्रांत के शहरों में महसूस किए गए हैं। 3 मार्च को आए भूकंप का केंद्र भूमि की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी कम गहराई वाले भूकंप प्राकृतिक टेक्टोनिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं और इस भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में ऐसे झटके असामान्य नहीं माने जाते। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान और अमेरिका युद्ध के बाद अब तक स्थायी समझौता नहीं हो सका है। हाल ही में दोनों मुल्कों के बीच शांति प्रस्ताव एक बार फिर खारिज हो गया है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान डील नहीं करता है, तो वह उस मुल्क को खत्म कर देंगे। साथ ही कहा है कि स्थिति अमेरिका के नियंत्रण में है और ईरान को खत्म करने के लिए उन्हें चीन की जरूरत नहीं है। एजेंसी वार्ता ने सीएनएन के हवाले से लिखा है कि ट्रंप पश्चिमी एशिया में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इससे पहले, ट्रंप के साथ बातचीत के बाद फॉक्स न्यूज ने कहा था कि वाइट हाउस होर्मुज जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए 'ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम' को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप को संघर्ष को सुलझाने के लिए हो रही बातचीत में ईरान के रुख से लगातार निराशा हाथ लगी है और अब वह बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि होर्मुज के बंद रहने से अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे रहा है।

ट्रंप के रक्षा बजट पर बवाल: ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद में घमासान, हेगसेथ बोले- अब भी हमारे हाथ में सारे पत्ते

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि तमाम तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट के बावजूद अमेरिका अब भी सभी पत्ते अपने हाथ में रखता है। सीनेट विनियोग उपसमिति के समक्ष रक्षा मामलों की सुनवाई के दौरान हेगसेथ ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ तीखी बहस की। इस बैठक में जॉइंट चीफ्स चेयरमैन डैन केन भी मौजूद थे। सुनवाई का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट, ईरान युद्ध की बढ़ती लागत, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से बढ़ती तेल कीमतें और चीन-यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रणनीति रही। हेगसेथ ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 47 वर्षों से ईरान अमेरिका पर हमला करता रहा है और परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर झूठ बोलता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार कार्रवाई करने का साहस दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की पूरी पारंपरिक नौसेना अब फारस की खाड़ी के तल में पड़ी है और मौजूदा स्थिति में अमेरिका के पास पहले से ज्यादा दबदबा है। हालांकि डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि यह युद्ध बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और अंत की योजना के लड़ा जा रहा है, जिसकी कीमत अमेरिकी जनता चुका रही है। वहीं सीनेटर पैटी मरे ने बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों के बीच भारी रक्षा खर्च पर सवाल उठाए। पेंटागन के मुताबिक ईरान

संघर्ष पर अब तक करीब 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, हालांकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने को लेकर उठा। वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम इस समुद्री मार्ग में व्यवधान के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका के पास 'सैन्य विकल्प मौजूद हैं', लेकिन वाशिंगटन अब भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है ताकि ईरान 'अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री डकैती' बंद करे। जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी माना कि ईरान अपनी सैन्य गतिविधियों के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाए हुए है, लेकिन उन्होंने सैन्य योजनाओं पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। सुनवाई में मिच मैककोनेल ने नाटो सहयोगियों और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब अमेरिका के विरोधी देश एकजुट हो रहे हैं, सहयोगियों से दूरी बनाना खतरनाक हो सकता है। वहीं चीन को लेकर भी अमेरिका की रणनीति पर चर्चा हुई। ट्रंप की संभावित बीजिंग यात्रा से पहले मैककॉनेल ने पूछा कि क्या ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी प्रतिबद्धताएं कायम रहेंगी। इस पर हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों जापान, ताइवान और फिलीपींस के साथ साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वत्वाधिकारी 'बात हिन्दुस्तान की' (पाक्षिक) पेपर के लिए मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती सोनी कुमारी झा, 23 रामकुमार गांगुली लेन, 2रा तल्ला कमरा नं. 203, पोस्ट- बी, गार्डेन, शिवपुर, हावड़ा-711103 (प. बंगाल) फोन नं.: 8902221434 से प्रकाशित एवं एल.एस पब्लिकेशन्स प्रा. लि.4, कैनल वेस्ट रोड, कोलकाता -700015 से मुदित, सम्पादक- वैद्यनाथ झा, फोन-9798848926 पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी, ईमेल/वेबसाईट - www.baathindustanki@gmail.com
(Owner, Printer & Publisher of 'Baat Hindustan ki' Smt. Soni Kumari Jha, 223, Ramkumar Ganguly Lane, 2nd floor, room no-203, PO_R.Garden, Shibpur, Howrah-711103, Mo. 9798848926 & Printed from L.S. publication private limited.4 no, canel west road, Kolkata 700015, Editor: Baidyanath Jha Mo. 9798848926, Email/Website: www.baathindustanki@gmail.com